The Times of India- 26- June-2022

Water low in canal, half of Delhi to suffer

New Delhi: Due to a sudden decrease in the availability of raw water at the Haiderpur channel, almost half of Delhi, including north, north-west, west and parts of south Delhi such as Delhi Cantt and command area of deer park, are likely to face a water crunch for the next few days.

"Delhi Jal Board is making all efforts to rationalise the water supply. However, water will be available at low pressure till the situation improves," DJB said, adding that the situation was being reviewed constantly.

DJB said the residents should store sufficient water in advance as per requirement. "Water tankers will be made available on request," it added. TNN

File No.T-74074/10/2019-WSE DTE

The Hindu- 26- June-2022

Assam floods: toll rises, Silchar still submerged

Rushing supplies: An Indian Air Force officer distributes relief material at a flood-hit area in Guwahati on Saturday. ▪ PTI

PRESS TRUST OF INDIA
GUWAHATI

The flood situation in Assam remained grim on Saturday with the death count rising to 118 and Silchar town in Cachar district remaining submerged for the sixth straight day, officials said.

Ten more people died in the past 24 hours – two each from Barpeta, Dhubri, Karimganj and Udalguri districts and one each from Cachar and Morigaon districts.

The total affected population declined to 33.03 lakh in 28 districts as against the previous day's figure of 45.34 lakh in 30 districts, a bulletin issued by the Assam State Management Disaster Authority (ASDMA) said.

The situation improved marginally in some districts as the water in rivers receded. However, the Brahmaputra at Dhubri and the Kopili in Nagaon were flowing above the danger mark, the officials said.

"The Cachar district administration is engaged in rescue operations in Silchar to evacuate marooned people, with priority being given to shift ailing persons to hospitals," Deputy Commissioner Keerthi Jalli said.

Food packets, drinking water bottles and other essentials are being air-dropped in the town by Indian Air Force helicopters. "This will continue till the flood situation improves," Ms. Jalli said.

Two drones have also been deployed in Silchar for carrying out flood inundation mapping and to provide relief material to the affected people. Eight NDRF teams comprising 207 personnel from Itanagar and Bhubaneswar, and an Army unit with 120 personnel and nine boats from Dimapur have been stationed in Silchar.

Shortage of food, water

Nearly three lakh people are in distress in Silchar with an acute shortage of food, clean drinking water and medicines, the officials said.

The worst flood-affected districts in the State are Barpeta, with 8,76,842 persons in distress, followed by Nagaon (5,08,475), Kamrup (4,01,512) and Dhubri (3,99,945), according to the ASDMA. The deluge has hit 93 revenue circles and 3,510 villages, while 2,65,788 people have taken shelter in 717 relief camps, it said. Relief material was distributed from 409 delivery points, the ASDMA said.

The Indian Express- 26- June-2022

Amid crisis, only 18% of treated waste water being reused in city

EXPRESS NEWS SERVICE
NEW DELHI, JUNE 25

WHILE THE reuse of treated waste water can lower the pressure on freshwater sources in the city, only a small fraction of the waste water that Delhi currently generates is reused.

As per Delhi Jal Board officials, the city reuses around 18% or 100 MGD (million gallons per day) of the 528 MGD of treated water generated at DJB's wastewater treatment plants. Treated water is supplied for horticulture purposes and washing buses, an official said.

Increasing the quantity of water reused would need a parallel network across the city to carry treated water to areas where it can be used, like agricultural land on the city's outskirts, the official said. The cost for a system of that sort is likely to be high, he said.

Demand for treated water for horticultural purposes is high particularly in the area under the New Delhi Municipal Council. The large gardens in NDMC area have decentralised STPs that supply water to them. The STPs have a combined capacity of 27 lakh litres per day, as per an official in NDMC's horticulture department. "Treated water currently being used is far below our original requirement of approximately 8 MGD for green areas. Of this, STPs supply around 0.5 MGD. We sometimes manage with tankers, but that does not suffice. The cost is high to bring the network from the DJB's STPs to these areas for reuse of treated water," the official added.

A DPCC report from May states that samples of treated water collected from 16 out of 26 waste water treatment units of DJB did not meet standards for disposal into water or land.

EXPLAINED E. DJB's push

The DJB will soon supply treated water to farmhouses. "We've received consent from a few RWAs, we are working on providing a network to supply water. Farmhouses in Chattarpur, Kapashera, and Bakkarwala will be connected to the network and are likely to consume around 20 MGD of water," said a DJB official. Efforts are also on to release treated water into lakes, another official said.

Haribhoomi- 26- June-2022

असम में बाढ़ की स्थिति गंभीर

24 घंटों में बाढ़ और भूस्खलन से 10 की मौत, अब तक 118

एजेंसी ▸▸| गुवाहाटी

असम में शनिवार को भी बाढ़ की स्थिति गंभीर बनी रही और इस प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 118 हो गई है। कछार जिले का सिलचर शहर छठे दिन भी जलमग्न रहा। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि पिछले 24 घंटों में बाढ़ और भूस्खलन के कारण 10 लोगों की मौत हुई है। इनमें बारपेटा, धुबरी, करीमगंज और उदलगुरी जिलों के दो-दो व्यक्ति और कछार तथा मोरीगांव के एक-एक व्यक्ति शामिल हैं। असम राज्य प्रबंधन आपदा प्राधिकरण (एएसडीएमए) द्वारा जारी बुलेटिन के अनुसार, 28 जिलों में बाढ़ प्रभावित लोगों की संख्या अब घटकर 33.03 लाख रह गई है, जबकि शुक्रवार तक 30 जिलों में यह आंकड़ा 45.34 लाख था अधिकारियों ने कहा कि कुछ जिलों में स्थिति में मामूली सुधार हुआ है। नदियों का जल स्तर कुछ हद तक कम हुआ है। हालांकि, धुबरी में ब्रह्मपुत्र और नगांव में कोपिली नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। उपायुक्त कीर्ति जल्ली ने कहा कि कछार जिला प्रशासन बीमार लोगों को अस्पताल पहुंचाने को प्राथमिकता देने के साथ सिलचर में बचाव अभियान चला रहा है। उन्होंने कहा कि वायुसेना के हेलीकॉप्टर की मदद से भोजन के पैकेट, पीने के पानी की बोतलें और अन्य जरूरी चीजें शहर में वितरित की जा रही हैं तथा यह कार्य तब तक जारी रहेगा जब तक कि स्थिति में सुधार नहीं हो जाता। बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री उपलब्ध कराने के साथ-साथ बाढ़ की स्थिति पर नजर रखने के लिए सिलचर में दो ड्रोन भी तैनात किए गए हैं।

■ कछार जिले का सिलचर शहर छठे दिन भी जलमग्न

आपदा प्रबंधन ने मोर्चा संभाला

सिलचर में ईटानगर और भुवनेश्वर से पहुंचे 207 कर्मियों के साथ राष्ट्रीय आपदा मोचन बल (एनडीआरएफ) के आठ दलों तथा 120 कर्मियों वाली एक सैन्य टुकड़ी तथा दीमापुर से लाई गई नौ नौकाओं को तैनात किया गया है। अधिकारियों ने कहा कि सिलचर में लगभग तीन लाख लोग भोजन, स्वच्छ पेयजल और दवाओं की भारी कमी से जूझ रहे हैं।

3,510 गांव प्रभावित

सिलचर में ईटानगर और भुवनेश्वर से पहुंचे 207 कर्मियों के साथ राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के आठ दलों तथा 120 कर्मियों वाली एक सैन्य टुकड़ी तथा दीमापुर से लाई गई नौ नौकाओं को तैनात किया गया है। बाढ़ से 93 राजस्व मंडल और 3,510 गांव प्रभावित हुए हैं, जबकि 2,65,788 लोगों ने 717 राहत शिविरों में शरण ली है। शिविरों में शरण नहीं लेने वाले बाढ़ प्रभावित लोगों के बीच 409 राहत केंद्रों से राहत सामग्री वितरित की गई।

312 मकान क्षतिग्रस्त

एएसडीएमए ने कहा कि पिछले 24 घंटों के दौरान कुल 312 मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं। बुलेटिन में कहा गया है कि बक्सा, विश्वनाथ, बोंगाईगांव, चिरांग, डिब्रूगढ़, दरांग, गोलाघाट, हैलाकांडी और कामरूप सहित कई स्थानों से बड़े पैमाने पर भूस्खलन की सूचना मिली है। इस बीच, रिलायंस फाउंडेशन के एक प्रवक्ता ने कहा कि राज्य में बाढ़ आने के बाद से वह असम सरकार को राहत सहायता प्रदान कर रहा है।

दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे
विविध कार्य

Dainik Jagran- 26- June-2022

रविवार विशेष

जल से जीवन संवारने की पहल

जल ही जीवन है, इस विचार का महत्व समय के साथ बढ़ता जा रहा है। कारण है धरती के नीचे कम होता जल भंडार। पृथ्वी पर जल तो बहुत है, लेकिन प्रयोग योग्य जल की बढ़ती कमी बड़ी समस्या है। जल संरक्षण ही वह उपाय है जिससे हमें प्रकृति प्रदत इस अनमोल उपहार का लंबे समय तक उपयोग करने का अवसर मिल सकता है। इसके लिए वर्षा जल का संरक्षण महत्वपूर्ण कदम है। रेन वाटर हार्वेस्टिंग से हम सभी परिचित हो चुके हैं। सरकारी भवनों व निजी भवनों में इस विधि को अपनाया भी जा रहा है। आज पढ़िए जल संरक्षण के लिए किए जा रहे दो नवाचारों के बारे में:

कल के लिए जल बचाने को नवाचार से खुल रहे द्वार

चट्टानों का सीना चीर बचाएंगे जल

जल संरक्षण के लिए किए जा रहे विभिन्न उपायों के बीच भोपाल में एक नवाचार की तैयारी है। शहर के मध्य में स्थित वन विहार में सरफेस वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम लगाया जा रहा है। इस प्रयोग से सतह के जल को एकत्र कर उसे चट्टानों के बीच की पाकेट्स (संग्रहण केंद्र) में एकत्र किया जाएगा। इसके लिए उद्यान में स्थित चट्टानों में 1,500 फीट की टेलीस्कोपिक बोरिंग कराकर इन पाकेट्स तक पानी पहुंचाने के लिए रास्ता बनाया जाएगा। इसमें ड्रिलिंग मशीन से बोर कर एक पाइप डाला जाता है। फिर इसके भीतर एक और पाइप डाला जाता है। वन विहार में चट्टानों के आसपास पानी रोकने को स्टाप डैम भी बनाया जाएगा।

विशेषज्ञों ने किया सर्वे: वन विहार में बनाई जाने वाली दोनों संरचनाओं से साढ़े चार वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में बरसने वाले वर्षा जल को संग्रहीत किया जा सकेगा। सरफेस वाटर हार्वेस्टिंग पर काम कर रहे मध्य प्रदेश जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मी) के सेवानिवृत्त विज्ञानी डा. एके वर्मा और सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड के पूर्व विज्ञानी देवेंद्र जोशी ने सर्वे पूरा कर लिया है। अगले वर्षाकाल में उद्यान में गिरने वाले वर्षा जल को संरक्षित किया जाएगा।

चट्टानों के नीचे जल भंडार: सर्वे के दौरान पता लगाया गया है कि वन विहार के चट्टानों वाले भाग में सतह से लगभग 500 मीटर नीचे बड़ा जलभंडार है। इस भंडार को फ्रैक्चर राक या चट्टानों की दरारों के माध्यम से संरक्षित जल प्रदान कर समृद्ध किया जाएगा। इस परियोजना के अंतर्गत स्टाप डैम में संरक्षित किए गए वर्षा जल को भी वन विहार की चट्टानों में किए गए ड्रिल से भू-गर्भ तक पहुंचा दिया जाएगा। जिससे वन विहार व आसपास के क्षेत्र को लाभ मिलेगा। डा. एके विश्वकर्मा ने यह भी जानकारी दी कि शहरी क्षेत्र में छतों से ही वर्षाजल एकत्र किया जाता है, क्योंकि यहां सतह पर गिरने के बाद कचरा, सीवेज, लोगों के आवागमन से जल प्रदूषित हो जाता है जिससे ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने पर भू-जल भी प्रदूषित हो सकता है। वन विहार में ऐसा खतरा नहीं है।

(भोपाल से प्रवीण मालवीय)

अतिरिक्त सामग्री पढ़ने को स्कैन करें

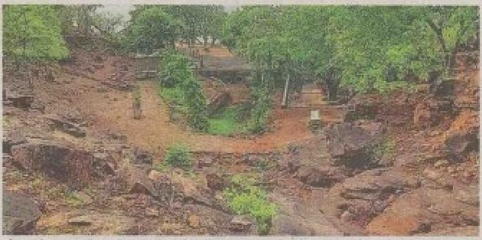

भोपाल स्थित वन विहार स्थित चट्टानें जिनके नीचे वाटर पाकेट है • सौ. वन विहार

प्राकृतिक नालों व झरनों की मैपिंग

सरफेस वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के लिए सर्वे करते विज्ञानी।

डा. एके विश्वकर्मा ने बताया कि वर्षाकाल में झरनों, प्राकृतिक नालों का पानी बह जाता है। इनकी मैपिंग की गई है। यहां पर स्टाप डैम बनाया जाएगा।

वन विहार का बड़ा हिस्सा चट्टानी है, जहां से प्रतिवर्ष वर्षाकाल में पानी बह जाता है। गर्मियों में पानी ऊपर ले जाना पड़ता है। इसे देखते हुए वर्षा जल संरक्षण के लिए सरफेस वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम और स्टाप डैम बनाने की योजना पर कार्य किया जा रहा है।

एचसी गुप्ता, निदेशक, वन विहार

हाईवे पर जल संरक्षण कर रहीं सावित्री

घर-गृहस्थी की जिम्मेदारियों को संभालते हुए मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर की सावित्री श्रीवास्तव ने भू-जल स्तर को बढ़ाने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम तैयार किया है। इस सिस्टम से देश के कई हाईवे पर करोड़ों लीटर पानी धरती की कोख में पहुंचाया जा रहा है। भारतीय राष्ट्रीय सड़क प्राधिकरण (एनएचएआइ) के साथ-साथ हाईवे निर्माण में जुटी देश की आठ बड़ी निजी कंपनियों ने भी इसे अपनाया है। जल शक्ति मंत्रालय ने रेन वाटर हार्वेस्टिंग के इस माडल को सराहा और सावित्री को वर्ष 2020 में वाटर हीरो सम्मान प्रदान किया।

परिवार से मिली प्रेरणा: सावित्री श्रीवास्तव के परिवार में वाटर प्यूरीफायर का व्यापार होता है। एक सिस्टम उनके घर में भी लगा है। उन्होंने देखा कि वाटर प्यूरीफायर में पानी शुद्ध होने के दौरान बड़ी मात्रा में व्यर्थ हो रहा है। यहीं से उन्हें जल संरक्षण के लिए सिस्टम बनाने का विचार आया। एक वर्ष के कड़े परिश्रम के बाद यह सिस्टम तैयार हुआ और वर्ष 2016-17 में ग्वालियर में 14 किलोमीटर लंबी शिवपुरी लिंक रोड पर इसका प्रयोग सफल रहा। इस क्षेत्र में भू-जल स्तर 150 फीट से 80 से 85 फीट पर आ गया। इसके बाद उनका सिस्टम एनएचएआइ तक पहुंचा। एनएचएआइ पहले हाईवे पर सोक पिट बनाया करता था। बाद में उसने इस सिस्टम को हाईवे के किनारे लगाना आरंभ कर दिया।

दिल्ली, चंडीगढ़ और सोनीपत के हाईवे पर हो रहा प्रयोग: सावित्री श्रीवास्तव का बनाया सिस्टम वर्तमान में हरियाणा-दिल्ली से राजस्थान को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 248 में द्वारका और मध्यप्रदेश-राजस्थान व उत्तरप्रदेश को जोड़ने वाले नेशनल हाईवे 552 पर प्रयोग की जा रही है। हाल ही में यह सिस्टम चंडीगढ़ में ओवर ब्रिज के नीचे लगाया गया है। छत्तीसगढ़ में रायपुर-बिलासपुर में भी इसका प्रयोग हुआ है।

(नईदुनिया से दीपक सविता)

अतिरिक्त सामग्री पढ़ने को स्कैन करें

चंडीगढ़ में ओवरब्रिज के नीचे लगी जल संरक्षण किट देखती सावित्री • सौ. स्वयं

ऐसे बनती है वर्षा जल संरक्षण किट

हाईवे के किनारे 60 से 80 फीट तक गहरे गड्ढे में एक छिद्र वाला पाइप डाला जाता है। इसके आसपास छह से आठ फीट गहरे गड्ढे में बनी आरसीसी संरचना में वर्षा जल को शुद्ध करने के लिए पत्थर, ईंट के टुकड़े, कोयला और रेत क्रम से रखी जाती है।

जल संरक्षण किट बनाते कर्मी।

शिवपुरी लिंक रोड पर सिस्टम की 40 किट लगाई गई हैं। ग्वालियर में औसतन 750 मिलीमीटर वर्षा होती है, यदि हम सड़क पर वर्षा का 55 प्रतिशत पानी भी बचा लेते हैं तो प्रतिवर्ष नौ करोड़ लीटर पानी की बचत होती है।

ज्ञानवर्धन मिश्रा, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर एवं प्रोजेक्ट आफिसर, शिवपुरी लिंक रोड, ग्वालियर